(घ) ऐसी गतिविधि की आशंका वाली गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बे प्लेटफार्म पर विधिवत रूप से मार्ग-रक्षण के अधीन और तालाबंद करके लाए जाते हैं।

(ii) प्रारंभिक स्टेशनों पर अनारक्षित यात्रियों का प्रवेश पंक्ति लगवाकर नियमित किया जाता है।

(iii) समय-समय पर लाइसेंसधारी भारिकों और अन्य समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध निवारक जांच की जाती हैं। नियम विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लाइसेंसधारी भारिकों के लाइसेंस बैज निलंबित/समाप्त कर दिए जाते हैं। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला छात्रावासों का निर्माण

†645. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार और वर्षवार कितने महिला छात्रावास निर्मित किए गए;

(ख) इन ग्रामीण महिलाओं को उनसे क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1996-97 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और छात्रवासों के निर्माण की मंजूरी देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना धन आवंटित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत होस्टलों की संख्या विवरण में दी गई है (नीचे देखिये)।

(ख) ये परियोजनाएं होस्टल वाले शहरों में रोजगार-रत महिलाओं को चाहे वे देश के किसी भी हिस्से से आयी हो, उपयुक्त, सुरक्षित और सस्ता होस्टल आवास उपलब्ध कराने के लिए हैं।

(ग) और (घ) स्वीकृति पात्र संगठनों से स्कीम की पद्धति के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करती है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग से लक्ष्य और राशि निर्धारित नहीं की जाती।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टल

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृत होस्टलों की संख्या 1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	1	-
2.	कर्नाटक	-	2	-
3.	केरल	1	2	4
4.	मध्य प्रदेश	1	-	-
5.	महाराष्ट्र	3	3	-
6.	मिजोरम	-	-	1
7.	उड़ीसा	-	1	-
8.	तमिलनाडु	-	13	4
9.	उत्तर प्रदेश	1	1	-
10.	पश्चिम बंगाल	-	-	1
	योग:	6	23	10

Technical assistance by UNDP

646. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether UNDP gives technical assistance to the Government on project/programme basis in the agricultural sector;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) how many UNDP assisted projects/programmes are currently being implemented in the State of Madhya Pradesh with details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Yes, Sir. The United Nations Development Programme (UNDP) gives technical assistance by supplying materials and equipment, training provide services of experts/consultants Organising of national and international workshops, fellowships, etc, through projects programmes in various fields of agriculture.

(c) the Following two UNDP assisted projects are being implemented in Madhya Pradesh, in addition to other States:

(i) Development and Strengthening of Integrated Pest Management (IPM) in India; and

(ii) Development of Oilseeds and Pulses Programme.

Details of these projects are given in the Statement.

Statement

UNDP assisted projects/programmes in Madhya Pradesh

Sl. No.	Name of the Project	Starting Year Duration	UNDP Contribution	Objectives
1.	Development and Strengthening of Integrated Pest Management (IPM) in India	1994 5 years	US $ 2,375,000	i) Upgradation of IPM technology for rice, sugarcane, oilseeds, pulses and vegatables; ii) Development of appropriate traning and extension modules for IPM technology; iii) Assistance in the formulation of national strategy for the IPM Programme in the 9th Five Year Plan.
2.	Development of Oilseeds and Pulses Programme	1996 2 years	US $ 2,600,000	i) Strengthening the technology application capabilities to demonstrate the cultivation of nutritionally better varieties of rapeseed; ii) Managing the problem of afflatoxin in groundnuts; iii) Increasing the capacities to produce planting materials for oil palm; iv) Train farmers and trainers in the Cultivation of oil palm and shattering resistant varieties of soyabeans, etc.

सौराष्ट्र क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विकास

647. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विकास के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम लागू किये गये हैं;

(ख) अब तक लागू किये गये कार्यक्रमों की क्या उपलब्धियां रही है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों की अब तक कोई समीक्षा की गई है;

(घ) उक्त योजनावधि के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में विशेषकर राजकोट मंडल में कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ड़) इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) (ख) और (ड़) गांधीधाम-भुज का आमान परिवर्तन बजट में शामिल कर लिया गया है और कार्य इस वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। भुज-नलिया के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण भी प्रारंभ किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) किसी क्षेत्र अथवा मंडल के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती। बहरहाल, इस कार्य के लिए 1996-97 के बजट में मुहैया कराया गया परिव्यय 11.01 करोड़ रु० है।

Central assistance for training centre at Mattupetty

648. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether a proposal for Central Assistance to the tune of Rs. 100 lakhs is pending before the centre to modernise and strengthen the present training centre at Mattupetty and Palakad to give practical training to the professionals in the field of cattle breeding frozen semen technology and fodder production;